mentary institutions and democracy I think you should hold mutual consultations in order to find out ways and means of creating public opinion and a situation in the country in which no one will dare to approach Members of Parliament or of the State Assemblies and compel them by use of force to resign. 1 would like Mr. Om Mehta, the Minister for Parliamentary Affairs, to take up this matter at the highest level. This is a common issue; this is not a party issue and we should all together face this challenge.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : I welcome the views expressed by Mr. Bhupesh Gupta and I assure him that I will convey his sentiments and views to the hon. Prime Minister.

## REFERENCE TO ALLEGED UNEARTHING OF A REVOLVER FACTORY IN THE DIESEL LOCOMOTIVE WORKSHOP AT VARANASI

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh) : I want to make a reference to a very unique and disturbing news. At the Diesel Locomotive Workshop in Varanasi there was found inside the workshop—the police raided the workshop—a revolver factory. According to the report the raid was conducted by Mr. J. P. Shukla, Deputy Superintendent of Felice. According to the Superintendent of Police Mr. B. K. Jain, the revolver factory was within the workshop and the supervisor, Shri Ram Bachan was arrested. His house was raided and there were found .32 and .38 bore revolvers. The news is published here and now it transpires that Mr. Ram Bachan's son was also arrested. He was found in Faizabad; he has been selling revolvers to students and going round. It was also alleged by the police that this fellow was engaged in smuggling revolvers via Nepal and China. According to the Superintendent of Police, Mr. Jain, Mr. Ram Bachan has accepted that he was selling revolvers and in the last two years he has sold 50 revolvers to the students and other criminals.

The Police Superintendent also said that the Chargeman's son was formerly in Nepal and he was smuggling revolvers from China. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You need not read the whole thing.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : I am not reading. Give me one minute more. When this smuggling business from Nepal ceased, he came to Varanasi and started this. If this news is correct, action should be taken. It is published in the paper "Janmorcha" which is the only co-operative daily being published. It has already got two years' standing. It is published simultaneously from Lucknow and Faizabad. I know the editor. There are very few such sincere and honest men. This is a very serious matter and I would like to draw the attention of the Government to this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The house stands adjourned till 4 P.M.

The house then adjourned for lunch at fifty-six minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past four of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

## RESOLUTION RE APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO SUGGEST REMEDIAL MEASURES TO CHECK THE FNFLUX OF RURAL POPULATION TO URBAN AREAS

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We will now take up Private Members' Resolutions. Shri Shankar Lai Tiwari.

**श्री शंकर लाल तिवारी** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :

"Having regard to the fact that daspite 25 years of planning, the social and economic gap between rural and urban areas has widened resulting in increasing flight of rural population to the urban centres in the fond hope of bettering their prospects, this House views this phenomenon with great concern and is of the opinion that a Committee of experts be appointed to find out the causes for, and suggest remedial measures to check, the influx of rural population to urban areas."

उपसभापति महोदय, इस प्रस्ताव को ठीक से समझने के लिये हम सरलता से इस प्रस्ताव को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग इसका यह है कि हमारे प्लानिंग को शुरू हुए, योजनाबद्ध कार्यक्रम को शुरू किये हुए इस

[श्री शंकर लाल तिवारी]

देश में 25 वर्ष हो गये। लेकिन इन 25 वर्षों में शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो असमानता थी वह और भी बढ़ गई है। असमानता की खाई और चौड़ी हो गई है। उसकी आर्थिक और सामाजिक असमनाता की खाई और भी चौड़ी हो गई है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि देहात के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं अपनी रोजी-रोटी के लिये। यह इसका पहला भाग है।

दूसरा भाग इस का यह है कि लोग इस असमानता के बढ़ने की वजह से रोजी-रोटी कमाने के लिये शहरों की तरफ जा रहे हैं। तीसरा भाग जो आपरेटिव भाग है वह यह है कि हम लोग यह जो हो रहा है शहरों की तरफ देहातों के लोगों की दौड़ हो रही है इसको हम चिन्ता से देखते हैं। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हम एक कमेटी स्थापित करें ऐक्सपर्ट लोगों की जो इस बात की जांच करें कि देहातों के लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं।

उपसभापति महोदय, आज हमको देखना है कि क्या हालत है। हमारे देश की आबादी लगभग 54-55 करोड़ की है जिसमें से 19.9 परसेंट स्त्री-पुरुष शहरों में रहते हैं और 80.1 परसेंट लोग देहातों में रहते हैं। या हम यह कहें कि हर पांच व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति देहात में रहते हैं और देहात में रहने वाला व्यक्ति अपने उदर निर्वाह के लिये, अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्भर रहता है। यह हालत है हमारे देश की। अब हम देखें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आमदनी क्या है। आज प्रत्येक व्यक्ति की प्रति दिन की आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में जितनी है उस से अगर तुलना करें शहर के लोगों की आमदनी से तो हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी से दुगनी और दुगने से अधिक शहरी क्षेत्र के लोगों की आमदनी है। हमारी जो राष्ट्रीय आय है उस का 50 परसेंट हमारे देहाती क्षेत्र से, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है। हमारे विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, देश की उन्नति की 1952 से, जब कि हम ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरु की थी। जब हम कोई भी देश के निर्माण और विकास की योजना शुरु करते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि हम शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों का विकास करेंगे और देहाती क्षेत्रों का विकास करने के लिये पहले पहले 1952 में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की शुरूआत की थी। एक-एक ब्लाक ले कर यह सोचा गया था कि हम गांवों के समूहों की तरक्की करें। कुछ तरक्की हुई और मैं मानता हूं कि गांवों में कुछ अवश्य तरक्की हुई। कुछ कुवें खोदे गये, कुछ सड़कें बनायी गयीं, कुछ पानी पीने के कुवें खोदे गये, स्कूल और हाई स्कूल खोले गये, अस्पताल और मैटरनिटी वार्डस खोले गये, लोगों को शिक्षित किया गया कि वे फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड्स का उपयोग करें, कुछ सिचाई के साधन बढ़े, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य था उन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को शुरु करने का कि वहां जो ग्रामीण आदमी रहता है किसान और मजदूर, गांवों में ज्यादातर वही लोग रहते हैं, किसान और किसानी पर आश्रित लोग ही रहते हैं तो हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य था कि वे गांव के लोगों की जनजागृति करें उन के विकास के द्वारा, जो हमारे देश की जनशक्ति है, जो गांवों में 80 फीसदी है वह उठ खड़ी हो अपने पैरों पर और वह खुद का अपना विकास करे और उन गांवों का विकास करे और उन को तरक्की करे। लेकिन क्या हुआ इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट। कुछ अस्पताल खुले, कुछ स्कूल बने, लेकिन वह आइटम्स आफ डवलपमेंट थे और हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स गांव की जनशक्ति को जागृत करने में असफल रहे। वे उस जनशक्ति को अपने पैरों पर खड़ा न कर सके। यह हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा फैल्योर रहा। इस के बाद हम ने दूसरा कदम उठाया और वह यह था कि गांवों की तरक्की के लिये हम ने सोचा कि हम पंचायत राज की स्थापना करें और यह सोचा गया कि देश में गांवों की तरक्की इन पंचायतों के जरिये से की जाए। इसके लिये तीन टीयर सिस्टम चला। एक था गांव पंचायत, गांवों के लेविल पर, दूसरा ब्लाक लेविल पर ब्लाक पंचायत और जिले के लेविल पर हम ने जिला पंचायत को शुरू किया। लेकिन उस का क्या नतीजा निकला। हमारे देश में जिस प्रकार से गांवों की बसाहट है उस में गांव समूहों में बसे हुए हैं। आप देखेंगे कि 8, 8 और 10, 10 गांवों में किसी एक जाति का प्रभाव रहता है तो इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी गांव पंचायतें गांव की पंचायतें नहीं बन सकी बल्कि वह जाति पंचायतें बन गई और वह जाति पंजायतें गांव को तरक्की की बात छोड़ कर झगड़े की जड़ बन गयी। कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ। कहीं-कहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा अनुभव है कि वह अधिकतर जाति पंचायतें हो गयी हैं और गांवों में झगड़े की जड़ हो गयी हैं। पहले गांवों में झगड़े नहीं थे, लेकिन पंचायतों के इलेक्शनों के बाद, उन की वजह से झगड़े बहुत बढ़ गये हैं और आपने देखा होगा कि इन पंचायतों के कारण कई जगहों पर मर्डर्स भी हुए हैं।

ब्लाक पंचायतों का क्या हाल है? वही हाल ब्लाक पंचायतों का है। मैं यह कहना चाहता हूं, जिला पंचायतें भी हैं। मंत्री महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने सुना है महाराष्ट्र में कुछ ठीक काम हुआ है जिला पंचायतों में लेकिन जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां तो जिला पंचायतें भी नहीं बनी इतने सालों के बाद भी। मैंने यह भी सुना है कि कई जगहों में जिला पचायतें भ्रष्टाचार के अड्डे हो गई हैं। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े हम। गांवों की बेकारी को दूर करने के लिये हमने एक कैश प्रोग्राम शुरू किया, एक नया आइटम था अभी दो-तीन साल पहले। एक तरक्की उससे हुई, इम्पलायमेंट लोगों को मिला। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मुझे कुछ ऐसे जिले भी मालूम हैं जहां पर कि रुपया

मार्च के अंत में भेजा गया और वहां के कलक्टरों ने रुपया वापस कर दिया। इस तरह का यह आपका क्रैश प्रोग्राम रहा।

तो उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, पंचायती राज, वे देहात में हमारी जन-जागृति में करने में, देहात में जन शक्ति को जाग्रत करने में, असफल रहे। लेकिन इस विकास के युग में दूसरी बात यह भी हुई—केवल शहरों की तरफ हम भागे। शहरों में बड़ी-बड़ी कपड़े की मिलें खुलीं। हमारे गांवों के बुनकर जो अपना जीविकोपार्जन बुनने के काम से, कपड़ा बुनकर करते थे वे बेरोजगार हुए। बड़े-बड़े चमड़े के कारखाने खुले—बाटा और टाटा भी इस रोजगार में आए। हमारे गांवों का मोची बेकार हुआ। बड़ी-बड़ी आइल मिल्ज खुलीं, गांवों में जो घानी के तेल का रोजगार करने वाले तेली थे वे बेकार हुए। बड़ी-बड़ी राइस मिल्ज खुलीं, क्या नतीजा हुआ उसका ? धान में हैंड पाउंडिंग का धंधा होता था हाथ से धान कूट कर, जो लोग इससे अपनी रोजी और रोटी चलाते थे वे सब बेकार हो गए। अब तो देहातों में आटे की मिलें लग गई हैं, घर की चकियां बंद हो गईं। एग्रिकल्चरल इम्प्लिमेन्टस मशीन से बनने लग गए—हमारे बढ़ई, लोहार, सुनार सारे के सारे लोग बेकार हो गए और उनके बाल-बच्चे और वे खुद शहरों की तरफ दौड़े जा रहे हैं रोटी की तलाश में। अब यह हालत है गांवों की।

अब हम जरा किसानों की दशा देखें, क्या हालत है। जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में उन्हें फर्टिलाइजर का उपयोग सिखाया गया, पेस्टिसाइड्स का उपयोग सिखाया गया, कुछ सिंचाई के साधन बने। उससे कुछ हालत उनकी दुरुस्त हुई। लेकिन फिर भी उसमें पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। उनकी हालत हम देखें तो उनका कुछ प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इनटर्म्स आफ रियल मनी देखें तो उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हुई, उनकी तरक्की नहीं हुई फसल की पैदावार बढ़ने के बाद भी। उनकी तरक्की नहीं हुई इसका कारण क्या था ? कारण यह था कि हमारे देश में बहुतायत से खेती होती है जानवरों के बल पर, पशु शक्ति के ऊपर। आज पशुओं की कीमत आसमान छू रही है। हमारे पास्चर्स खत्म हो गए, विलेज के पास्चर्स, गाय के गोबर स्थल खत्म हो गए, हम ने उन्हें खत्म किया खेती के लिए जमीन बांटने के लालच में। हमारे जानवर भी कम हो गए, जहां पास्चर्स थे वे भी बहुत कम हो गए। इसलिए जहां हमारी कैटल ब्रीडिंग (breeding) होती थी, जहां से हमारे पशु निकलते थे, खेती के काम में आते थे, वे कम हो गए, उनकी कीमतें बढ़ गईं, फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ गई, वाटर रेट्स भी आपने बढ़ाए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, उसका उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन चूंकि कीमत आप कंट्रोल करते हैं, शासन खेती की चीजों की कीमत को मुकर्रर करता है और जो शासन कीमत को मुकर्रर करता है, वह उसके उत्पादन के खर्च के ऊपर ध्यान नहीं देता।

प्रोडक्शन कास्ट को नहीं देखते। मिल में कपड़ा बनता है। उसकी कीमत मुकर्रर करते वक्त आप प्रोडक्शन कास्ट को देखते हैं, लेकिन किसान की उपज की कीमत तय करते वक्त आप कन्ज्युमर का इन्टरेस्ट देखते हैं, उत्पादन खर्च को देख कर तय नहीं करते, उसकी कीमत कन्ज्युमर-ओरियेन्टेड है; क्योंकि कन्ज्युमर शहर में रहता है, आर्गनाइज्ड है, वह हल्ला करना जानता है, मोर्चा निकालना जानता है, किसान नहीं। आपको चाहिए था कि प्रोड्युसर-ओरियेन्टेड कीमत रखते। किसान बेबस है, बेजुबान है, गांव का रहने वाला है, उसमें संगठन की शक्ति नहीं है। वह सरकारी नौकर की तरह अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आन्दोलन का रास्ता नहीं ले सकता। वह अपना स्टेटस और तनख्वाह बढ़ाने के लिए डाक्टरों और इंजीनियरों की तरह हड़ताल नहीं कर सकता। वह अपने काम के घंटे कम कराने के लिए रेलवे के वर्कर्स की तरह स्ट्राइक नहीं कर सकता। वह बोनस की मांग करने के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह घिराव करना नहीं जानता। वह उद्योगपतियों की तरह आर्टीफीशियल स्केयरसिटी पैदा करके मुनाफाखोरी करना नहीं जानता। इसका फायदा आपने उठाया है; क्योंकि वह बेजुबान है, जिसकी वायस नहीं है, संगठन नहीं है। इसका कारण क्या है, यह हमें देखना पड़ेगा। क्या कहीं हमारी गलती हुई प्लानिंग करने में ! उपसभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी प्लानिंग के सूत्रधार थे, जिन्होंने 1952 से प्लानिंग की, वे सब शहराती लोग थे, उन्हें गांवों का अनुभव नहीं था, देहाती क्षेत्रों की समस्याओं का अनुभव नहीं था और इसी लिए सारी प्लानिंग वन-साइडेड हुई। उद्योग-धन्धे शहरों में लगे, गांवों की तरफ नहीं गए। मैं मानता हूं कि थोड़ी तरक्की हुई; लेकिन कम्पेरिजन में विलेजेज की बहुत कम तरक्की हुई। मैं कह रहा था कि शहर के लोगों ने गांवों की प्लानिंग बनाई। उनको अनुभव नहीं था, देहात की समस्याओं का ज्ञान नहीं था और इसलिए हमारी प्लानिंग अधूरी रही। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमारी तमाम लीडरशिप हर लेवल पर शहराती रही। उन्हें शहर के लोगों की आवाज का, उनके संगठन का ध्यान था। इसलिए उन्होंने शहरी क्षेत्र पर ध्यान दिया और देहाती क्षेत्र को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया।

आगे क्या हुआ ? अभी कुछ दिन पहले उन अखबारों ने, जिनके मालिक इस देश के उद्योगपति हैं एक नया नारा लगाया रुरल रिच का। उन्होंने इस बात का नारा लगाया कि देहात के लोग बड़े सम्पन्न हो गए हैं, देहात में बड़ी

[श्री शंकर लाल तिवारी]

सम्पन्नता आ गई है। यह नारा क्यों लगाया गया ? इस के पीछे, जैसा मैंने कहा, वे अखबार हैं, जिनका स्वामित्व इस देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। उसका बड़ा कारण यही था कि सरकार का ध्यान टैक्स लगाने के लिए उनके ऊपर से हट कर बेचारे और बेजुबान गांव के लोगों की तरफ जाय। ऐसा हुआ भी। हमारी सरकार भी उस झांसे में आ गई और गांव के लोगों पर टैक्स बढ़ने लगे। गांव का लगान बढ़ा, वाटर रेट्स बढ़े, एग्रीकल्चरल टैक्स लगा। कैपिटलिस्ट प्रैस की शिकार हमारी सरकार हुई और कैपिटलिस्ट प्रैस का शिकार जो अपने को डाउनट्रेडेन का चैम्पियन कहते हैं--भूपेश गुप्त यहां नहीं है—वे भी हुए, जब वे कुलक्स और मोनोपोलिस्ट्स को एक साथ क्लब करने लगे।

कहां कुलक है इस देश में ? मालगुजारी गई, जमींदारी गई, जागीरदारी गई, जमीन की सीलिंग लग गई। आज कोई कुलक नहीं है इस देश में। यह देश छोटे-छोटे किसानों का है। उनके पास कोई आल्टरनेटिव साधन नहीं है। अगर होता तो बहुत से किसान अपनी किसानी का धंधा छोड़ देते। ये लोग भी शिकार हुए हैं।

उपसभापति महोदय, चूंकि प्लानिंग में सब शहरी लोग थे, प्लानिंग करने में जिनका हाथ था वह अरबन एरिया के लोग थे। उन्होंने अपने वर्ग के लोगों को बचा कर रखा है। लैंड सीलिंग लागू हुई देहात के लोगों पर, क्या अभी तक अरबन सीलिंग लागू हो पाई ? मैं कहना चाहता हूं कि अरबन लीडरशिप ने अपने लोगों को बचाया है जो शहरों में रहते हैं।

दूसरी पिक्चर देखिये शहरों की। शहरों की पिक्चर यह है कि रोज शहर बढ़ रहे हैं। एक से एक शहर बढ़ रहे हैं और उन शहरों में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तनख्वाह आप देखिये। बड़ी-बड़ी मोटी तनख्वाहें एक मजदूर जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको मिलती हैं बनिस्बत किसानों के। दूसरे बैनिफिट्स हैं शहरों में। रहने को साफ सुथरा मकान मिलता है, पक्का मकान मिलता है, बिजली की रोशनी से चमचमाहट होती है, डामर की पक्की सड़कें और आमोद-प्रमोद के साधन हैं। इन सब के लालच में आकर गांव का आदमी आज शहरों की तरफ जा रहा है।

उपसभापति महोदय, जहां पर भी उद्योग-धंधे खुलते हैं--फरीदाबाद को ही देख लीजिए--वहां पर एक नया शहर हो जाता है। वहां भी चमचमाहट है। अच्छे साफ-सुथरे और पक्के मकान रहने के लिए मिल जाते हैं तो बेजुबान किसान, बेबस ललचाई आंखों को देखता है। उसका लड़का, उसका बच्चा आज खेती करना नहीं चाहता है। वह जाना चाहता है शहरों की तरफ, शहरों की खुशहाली और अच्छी जिन्दगी देख कर।

तो उपसभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि हमारे शहरों की आबादी बढ़ रही है, हमारे शहर आबाद हो रहे हैं और गांव उजाड़ हो रहे हैं। इन गांवों को उजाड़ होने से बचाया जाय। हमें इन कारणों में जाना पड़ेगा कि हमारी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से हमारे देहात का आदमी शहरों की तरफ जा रहा है। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि इन सारी चीजों को जिन को हम चिन्ता से देखते हैं, इसके लिए एक विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाय, जो इस बात की जांच करे कि आखिर यह गड़बड़झाला क्यों हो रहा है। क्यों वह अपने गांवों में नहीं रहना चाहते हैं। वह कमेटी इन सारी बातों की जांच करके सुझाव दे कि इस तरह से शहरों की तरफ जो लोग भाग रहे हैं, उनको रोका जाय।

उपसभापति महोदय, यह सीधा सादा प्रश्न है और इसकी बड़ी अहमियत है जब कि शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस हाउस के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को सहानुभूति से देखेंगे, ग्रामीण जनता के हित में देखेंगे और इसका पूरे रूप से समर्थन करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There are two amendments in the name of Shri D. S. Patil. He may move them.

SHRI D. S. PATIL (Maharashtra) : Sir, I move :

1. "That in line 6, for the words 'Committee of experts' the words Committee 'consisting of Members of Parliament and experts, be substituted."

2. "That at the end of the Resolution, the following be added namely :

'with direction to submit its report before the expiry of six months from the date of its appointment".

The questions were proposed

SHRI L. MAHAPATRO (Orissa) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I followed my friend, Shri Shankar Lai Tiwari's speach who moved this Resolution and 1 find that he has divided his own Resolution into three parts, the first part being that there has been a social and economic gap between the rural and urban areas, the second part being that there has been a great influx of the rural population into the urban areas and the third part being thai a Committee of experts should be appointed to go into the causes and suggest remedial measures.

Now, Sir, as far as the first two parts are concerned, when I read it, I saw very great

force in what he has said, particularly where he has said that there has been a very bad planning during all these twenty-five years and it is also an undisputed fact that this planning has been the cause for this gap, social and economic, between the rural and the urban areas. But, Sir, as I heard him, I gained the impression that he wanted to speak or rather wanted to plead for the rural rich, the rich peasants in the rural areas, and I would come to that later when I will discuss about what all he has said and what ordinarily his Resolution would mean.

As far as the second thing is concerned, that is, the influx of the rural population into the urban areas he is frightened by the big number that comes from the village side to the urban side. But, as I see it, the number is not so big. Even today, Sir, it is a big number in the village side and I quite agree with his feelings that that population which is still there in the village side has not been properly attended to and there is a lapse on the part of the planners in relation to this aspect of the matter.

Now, as far as the third part is concerned, the operative part as he calls it, [ do not agree with him at all that there is a necessity for a committee, because the causes are very well-known and the remedies are also known and they can also be got at. As a matter of fact, it was not done earlier. But, when it was done, that is, at the time of the mid-term appraisal of the Plan, it was found that most of our planning was done in a wrong way just as he pointed out the examples of the Community Development and the Panchayati Raj programmes. Therefore, the causes are known and the remedies are also known. But the whole trouble is in doing these things.

DR. K. MATHBW KURIAN (Kerala) : It is the lack of political will

SHRI L. MAHAPATRO : Having known these things, are we prepared to do something in that direction and prevent these people from running away from the villages to the towns ? I think the mover of this Resolution has so beautifully framed it which conveys a lot of meaning. He says that there is a gap between the rural and the urban areas which has widened resulting in increasing flight of the rural population to the urban centres in the fond hope—he has used the words "fond hope"—of bettering their prospects. Now, there are two groups of people who rush to the towns and both these groups run to the towns in the fond hope of bettering their prospects. One is the group of people who have made the best use of all these plans and what all these plans have done during all these years and they have exploited the people and these people think that better prospects are to be seen in the town side and so, they go to the town side and resort to better methods and more advanced methods of exploitation.

That's why they run. And the other class is a class which got frustrated in all its attempts to make a living there. At last, it had to run away with a view to see if it can get a small hutment, by constructing it with broken bricks that can be had from the debris of an old house or a building that was there in the town, or to save itself from social oppression.

After reading this Resolution, I am reminded of one of my experiences. Frankly speaking, I came to Delhi for the first time in 1963, when there was a great march by the CPI. When I returned to my place, many in the village asked me, "What did you see in Delhi ?" I said that to know Delhi or to see where Delhi is you can just be in a railway compartment and you see small huts of so many people with broken roofs and such things, and then you see a very beautiful city. That is what I narrated to them about our planning.

Then, again, in 1964 I had to go via Hyderabad to Bombay for a Party Congress. There I saw the twin cities of Secunderabad and Hyderabad, and very close at a distance of about two kilometres small hutments, people in rags, skeletons. When I returned, 1 narrated to them what the South is like or what our Nizam was. These social conditions are there.

My friend, while describing this Resolution, was making a very peculiar exposition by saying that the rural side has to be kept intact, pastures have to be kept in fact, and so on, or having pure ghee by having two or three cows and not going to a dairy farm. He is very conservative in his ideas, somehow or other. I am not prepared to agree with him that we should continus to have old methods. We should take to modern methods and modern things. But one difficulty faces us in the widening gap in between the rural and

[ Shri L. Muhapatro ]

the urban side. But I see no great difficulty in solving the problem.

You know. Sir, that an urban area is that where one has certain amenities or where houses are built in a particular way. That is what we call an urban area. As far as rural area is concerned, that is an area of old India which does not have these facilities and these amenities. And if the gap is there, the rural area continues to be the rural area. But it can be converted into urban area if you give all these amenities that are there. When I went to G.D.R., people asked me, "What is that you saw tnere ?" I told them that I did not see a village; I saw small towns and big towns. Unfortunately, we are not prepared to make a move in that direction. That's why we find this widening gap, and that is why we hear certain statements made by some people that there should be a fight, there should be a war between he rural and urban people, and in fact it is raked up many a time on some issue or the other. Therefore, my feeling is that instead of listing up the difficulties that the rural people face, we should see what can be done to come over these things. But that cannot be done by having a committee.

I want to place before you certain things, it is true that planning so far done has not yielded the desiied effect. The agriculture of our country or the agrarian problem of our country has not received the proper attention and the result is that we see so many classes developing in the villages. The worst suffering class is the rural proletariat or the working class, the productive force. They have not been given any opportunity of making a living either by daily wages, tilling the land or anything else. The village artisans have also been turned into the rural proletariat. These people need the best of attention. It is not being done. There was a time when our planners thought that pumping of money to the rural side would bring in a dynamic change in the agrarian production of the country. What has happened ? It went into the coffers of a privileged few who made the best use of it by turning themselves into moneylenders and ultimately coming to the towns for turning themselves into industrialists and better exploiters. That has been the ultimate go of these people. The people who really needed some money have not got it even after the nationalisation of banks. They run from one commercial bank to another and all the hurdles which have been pointed out by the Rural Agricultural Credit Survey Committee are still there. They have not been attended to. The rule that a propertied man alone would be entitled to got the money is still there. Rural indebtedness has been growing. They have not been able to extricate themselves from the rural indebted-less. There should be a measure or a law providing for writing off the indebtedness of those persons who are incapable of paying. 1 think a committee to go into this aspect would be the best idea. It appears that in one of the American offices, there was a slogan written on the walls. It read as "promptitude is our motto". After some time, when that gentleman went to that office, he found that the slogan had been replaced by another slogan reading "Committee is our motto". The whole point is that we should no take the matter before a committee for the purpose of delaying it. You know that the agitational fervour in the earlier part is lost when a committee is appointed and you can quieten the people after giving than a big volume of the committee report. That is not what I am interested in. I am interested in the result.

Now I come to drinking water. There is a small place in my State. Most of you must have gone there Ministers do often go there. The Prime Minister goes there very often. It is Goplapur-on-sea This town is a very good health resort ever since the British days. Near the town, there is a very good population of fishermen community. They do not have drinking water. It is an important place and all the dignataries go there. What do you say about this type of planning ? Shall I satisfy myself by saying: "Nearest the church, furthest from God ?" Shall I say that we are simply blind to what is happening in our country ? We want to be here. We want to rest content by making some speeches.

With that, we think our busine s is done. But if we have really to see anything, then these are the things that we will have to see— the rural indebtedness, the rural proletariat and their difficulties about drinking water, hutments, land etc. These can be looked into, and the conditions of the rural folk bettered. And that is the best way of checking the

influx of these people from the rural side. I am happy that the rural proletariat is organising to overcome its sorrow.

SHRI R. K. MISHRA (Rajasthan^ : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am sorry to say that I cannot associate myself with the Resolution which Hon. Shri Tiwari has moved. The Resolution is based on misconception; and wrong reading of the situation. And I got he impression from his speech that he was trying to divide the poor people in the rural and urban areas in a bid to defend the affluent rich in the rural areas, whose existence he has denied. It is really an emazing statement to make, Mr. Deputy Chairman, Sir, that the conditions of he poor in the rural and the urban areas of our country have remained almost stagnant during the last two decades. I would like to point out to you, Sir, that during the lost 25 years, we find that in the urban areas, the per capita consumption of the poor has in fact declined while the per capita consumption of the poor in the rural areas has slighly increased. This does not mean at all that the condition of the rural poor is in any way better. It remains as distressing as it was 25 years ago. But in 1952, in the fourth round of the National Sample Survey, the per capita consumption of the lowest 30 per cent of the population in the rural areas was Rs. 11.18 and in 1967-68, the year for which the latest figures are available, that is the 22nd round, the per capita consumption of the lowest 30 per cent of the population i I the- rural areas was Rs. 11.31. Compared to this, la the urban areas, in 1952, the per capita consumption was Rs. 13.96 while in 1967-68, the per capita consumption of the lowest 30 per cent of the urban population was Rs. 13.74. Mr. Deputy Chairman, Sir, it requires no expert knowl dge because enough expertise has gone into the study, to find out the reasons of poverty as well as to locate the areas and sect inns of population where poverty resides both in the rural "and in the urban areas. It is fantastic to suggest that while urban areas have developed during the last 25 ; ears, the rural area as a whole has remained neglected. As you know, Sir, as compared to 1951-52, production in agriculture has increased it 1964-65 by 66 per cent, and since then the increase in agricultural productio I is from 3 to 5 per cent. And we are also aware as to who has appropriated the increase in agricultural production. It has not gone to the rural poor. It has been appropriated by a very small section of people livmg in rural areas, the big landlords and the kulaks. The kulaks do exist. The big landlords do exist. The big peasants do exist; they have been trying to use the name of kisans as if kisans are a homogeneous community in which all incomes are equally distributed. No greater disservice can be done to the poor people living in rural areas than to allow this farce to be played upon them. Well, Mr. Deputy Chairman, Sir we know that thousands of crores of rupees have been invested in irrigation projects. And what is the condition of our irrigation projects?

I have got figures for one year. In one year our irrigation projects have lost Rs. 130 crores. A subsidy is given to the rich peasants who utilise the irrigation potential. What is the contribution which the agricultural sector, primarily the rich peasants, make to the total resources deployed for development. Only one per cent of the total output in the agricultural sector is contributed by them by way of direct taxation.

Mr. Deputy Chairman, Sir, it is true thai people in the rural areas are poor. Their conditions are really appalling. But, it is so because there is unequal distribution of incomes, there is concentration of ownership of land in the hands of a small section of population and because the promises of land reforms made during the last 25 years have not been implemMtea. It is so because in the eastern region of India millions of our poor people are living in conditions of insecure tenure, because share-croppers are denied their rights in the share of the crop, because thousands of people are evicted in every agricultural season from the land which is given to them Iron year to year. Agricultural has become tunerativc.The richer amongst the .agriculturists want to grab as much la i ' as possible in their own hands. We are also aware of the.fact that in of the: laws passed and the constitutiot-al protection given, these laws have remained on paper. The ceilkng law also exists o'\ paper only. It ha; not been implemented as tively as it should have been done.

We are also aware of the rural poor that come to the urban areasbeause as we proeced with .atioo, the industrial labour force concentrated in the

[Shri R. K. Mishra] urban areas is likely to increase. That is why by 1980-81 the percentage of urban population to the total population of this country will increase from 19.1 per cent to around 24 per cent.

Sir, if we really want to improve the living conditions of the rural people what is necessary is to see that gainful employment is created in rural areas. It is also necessary to see that the ownership of land must be distributed in such a manner that it is available to a large number of people, and that the entire agricultural strategy which has been pursued during the last ten years should be recast in favour of the small and marginal farmers.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am making this suggestion keeping in view that we must improve and increase our agricultural production if we want to strengthen the base of economic independence and if we want to achieve self-reliance. There is enough evidence available to show that mechanisation of agriculture has started giving diminishing results. In Punjab and Haryana the productivity of land during the- last two years has not increased and in certain cases it has decreased. If we really want to improve food production, it is necessary to intensify our agriculture....

SHRI RANB1R SINGH (Haryana) : Who is feeding the country ? Punjab and Haryana.

SHRI R.K. MISHRA : Chaudhari sahib, these are facts.

It is true, Mr. Deputy Chairman, Sir, that Punjab and Haryana are contributing a substantial part of wheat produce in this country specially that part of wheat which goes in the public distribution system. But the point I am making is that this pattern of ownership has started yielding diminishing returns in terms of productivity. If you want to increase productivity in land now, it is necessary to give inputs, it is necessary to give new techniques to small and marginal farmers because you have reached a stage where the small farmer in eastern U.P the marginal farmer in Bihar could contribute to the total agricultural production in the country. If your agricultural strategy is not changed, if you do not provide the inputs and credit in his hands, agricultural production will not increase.

I am not in any way denigrating the valuable contribution that the enterprising farmers of Punjab and Haryana have made, and especially Punjab, though I cannot say the same of Haryana because last year while the farmers of Punjab did contribute almost their share to the public distribution system, the farmers of Haryana because either of natural reasons or because of other reasons of which we are aware, failed to do so.

Mr. Deputy Chairman, Sir, if we want to maintain the public distribution system in this country, then also it is necessary to strengthen the economic base of small and marginal farmers, because 4.7 million tonnes of wheat which our public agencies succeeded in procuring last year—a substantial part of it—came from small and marginal farmers. The rich farmer, knowing fully well that he will hold back wheat in his own godowns, forced the Government to reverse its policies and forced a situation in which prices would rise; he will make money; he can hold back the stocks. Therefore, if we want the public distribution system and the public procurement policies to succeed, then also it is necessary because the middle and the small farmer is the really dependable ally of the many crores of people of this country who must have two square meals a day, who must have adequate foodgrains.

Mr. Deputy Chairman, Sir, 1 would also like to point out that this migration from rural areas to urban areas is also partly due: to the deterioration in the conditions in which our small-scale and handloom industries in the rural areas are existing at present. Also, traditional handicraft and handloom industries have not been sufficiently modernised; enough funds have not been made available to them. The greater the development of capitalist farming in this country the greate.- will be the influx from rural areas to urban areas because, by its very nature mechanisation of agriculture displaces the labour force which is employed on land. Therefore, it is necessary to see that the pattern of agricultural development is of a nature which would provide gainful employment to the rural people at their own place. Of course, if we really want that the rural poor should get gainful employment, then, in addition to redis-

tribution of land and restructuring of land relations, provision of inputs and development of cottage and handloom industries and their modernisation, it is also necessary to undertake a very vast scheme of construction activities in the rural areas. Construction provides the largest amount of employment in our own country. Now, a decision was taken by the Congress Party some time ago to allot house sites to the landless and the poor people in the rural areas. If this decision is implemented—which I wish and hope may be implemeted if there is any organisation and if there is enough power in the hands of these poor people to whom this promise has been made—then millions of people can be provided gainful employment in the rural areas. From my own State of Rajasthan, especially from Jaipur, thousands of construction workers come to Delhi every year and they are engaged in construction activities in Delhi. If gainful employment could be provided to them in rural areas they would not like to come here and live here in dismal condition {Time bell rings.) Therefore I would suggest that cons ruction activities should also be given adequate importance and funds should be provided for them.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the minimum needs programme which is art integral part of the Fifth Year Plan also see'ks to take care of some of trie pressing aspects of rural poverty. I hope it will be possible to find funds for the minimum needs programme but here I must caution that the minimum needs programme should not be a social welfare programme but it should be a productive programme so that the money invested in it is productively used and productive assets are built and gainful employment is created, i am happy to know last year—Mr. Mohan Dharia was in charge of that programme for providing employm. the rural as well as in the urban areas—some work was done.

In conclusion I would like to suggest, Mr. Deputy Chairman, that the problem of poverty is not merely the concern of planning or the Planning Commission. The Approach to the Fifth Five Year Plan as well as the Fifth Plan document I would like to submit, ana!) great detail the causes of poverty, identify in great detail the sections of the population where poverty resides. It is the drought-prone areas, it is the hilly areas, it is areas with demographic pressures, it is the areas where the agro-climatic conditions are such that people are not able to employ themselves gainfully. It is among the Adivasis, the Harijans, the landless in the rural areas where poverty resides. Therefore the programmes have to be so conceived that these people are benefited. I am convinced in my own mind that whatever the Planning Commission may do, whatever financial allocations may be made, these programmes cannot be effectively implemented unless these sections of the population are organised. And it is here that the challenge must be accepted by all of us who show concern for the poor people. Unless these people arc organised, these programmes will remain staff-oru-.ited programmes and a large part of the funds will be wasted in running the bureaucratic machinery which goes with every programme. Therefore poverty can be fought only by mobilising enough people and not by appointing a Committee of experts because enough knowledge is available about what should be done. The challenge is what should 'x done must be done on the ground.

**श्री कृष्णारावनारायण धुलप** (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से इस सम्माननीय सदस्य शंकरलाल तिवारी जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं जिससे हमको अपने विचार सदन के सामने रखने का मौका मिला है। उन्होंने जो सवाल उठाया है और उसके समर्थन में जो भाषण इस सभागृह में किया, यद्यपि उनकी सारी बातों से हम सहमत नहीं हो सकते, तो भी उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि इस सवाल के बारे में हमें भी अपनी राय देने का अवसर मिला है।

मुझे एक बात पर जरूर दुख होता है कि स्वाधीनता मिलने के 25 वर्ष के बाद भी हमारी सरकार ने अभी तक देहाती इलाके में जो बेरोजगारी है उसके बारे में अभी तक मामूली जांच भी नहीं की, जो कुछ उसके बारे में कार्यवाही करनी जरूरी है अभी तक उन्होंने नहीं किया है। इस सदन में एक सम्माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था जिसके बारे में क्वेश्चन न० 394 तारीख 9 अगस्त, 1973 के उत्तर में शासन की तरफ से बताया है —

5 P.M.

SQ. No. 394 dated 9th August, 1973, reply says :—

"The Government have not so far made any precise estimate of the extent of un employment a id under it in the rural areas."

यानी स्वाधीनता के 25 साल के बाद भी अभी तक शासन ने एस्टीमेट भी नहीं बनाया। इसका मतलब

[श्री कृष्णरावनारायण धुलप]

यह होता है कि देहात में जो बेरोजगार लोग रहते हैं या जो अर्द्ध-रोजगार प्राप्त लोग हैं उनके बारे में जो कार्यवाही करना जरूरी है शासन उसको अभी तक करने के लिए तैयार नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने और सरकार ने कई समितियां मुकर्रर की हैं जिनकी रिपोर्ट उनके सामने होगी। मेरे सामने एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट माननीय बी० भगवती ने मई 73 में शासन को दी थी —रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन अनएम्प्लायमैंट। उसमें उन्होंने देहाती इलाके में जो बेकार लोग हैं, अर्द्ध-रोजगार-प्राप्त लोग हैं उनके बारे में बहुत कुछ स्टेटिस्टिक्स दी हैं और कुछ सिफारिशें की हैं। उसको भी एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह बड़े दुख की बात है।

यह बताने की यहां जरूरत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की कई समस्याएं हैं, खासकर खेती के बारे में, जिसका सवाल कई सम्माननीय सदस्यों ने उठाया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वे देहाती लोग, ग्रामीण लोग शहर में क्यों आते हैं, यह पहले सोचना जरूरी है। देहात से जो पढ़े लिखे शहर में आते हैं रहने के लिए, उनके बारे में सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, वे अपनी तरक्की के लिए आते हैं। बाकी रहे दो किस्म के लोग जिनके बारे में इस सदन को सोचना जरूरी है। एक तो वे पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी जमात के लोग जिनके लिए वहां रहना सामाजिक दृष्टि से भी मुश्किल होता है। वे लोग वहां से शहर में आते हैं। उनमें खासकर हरिजन लोगों का सवाल है। तिवारी जी ने बताया कि ग्रामीण संस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि वे जातीय संस्था बन गई हैं, जिसके हाथ में ग्राम पंचायत की बागडोर होती है, वे अपने अपने लोगों की लिए सब कुछ करते हैं। पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कुछ है नहीं, न सामाजिक दृष्टि से, न आर्थिक दृष्टि से। देहात में उनके लिए जमीन नहीं है। वे काश्तकार नहीं हैं और सामाजिक दृष्टि से भी उनके ऊपर अन्याय होता है। वे लोग जब देखते हैं कि दूसरे नजदीक के देहात में अन्याय होता है तो वे खुद का देहात छोड़कर शहर में आना शुरू करते हैं। शहरों में उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं हैं, कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, न गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करने को तैयार है। वे लोग, जो कुछ उनके पास है उसको लेकर शहर में आते हैं। एक तो वह केटेगरी है। दूसरे लोग वे हैं जिनको वहां काम नहीं मिलता खेत में दो तीन, चार महीने से ज्यादा काम उनको नहीं मिलता जो बड़े बड़े जमींदार रहते हैं उनकी मेहरबानी के ऊपर उन लोगों को बड़ी लाचारी से रहना पड़ता है काम मिले तो काम करते हैं अन्यथा उनके लिये गुजारा करना भी सम्भव नहीं होता है। फिर उनकी अर्द्ध-बेकारी की हालत शुरू होती है। एक तो वे लोग हैं जिनका उल्लेख मैंने पहले किया था। उसके बारे में हमारे पास एस्टीमेट ही कुछ नहीं है, न गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ किया है। दूसरे जिनको बिल्कुल काम ही नहीं मिलता है वे देहात छोड़कर शहर में आते हैं। इस तरह दो किस्म के लोग शहर में आते हैं—एक तो वे जिनके ऊपर सामाजिक अन्याय होता है और आर्थिक दृष्टि से उनके लिए रहना मुश्किल है, और दूसरे जिनको वहां काम नहीं मिलता।

उसके बाद शहर में शहर की समस्याएं शुरू होती हैं। उनके लिए शहर में नौकरी नहीं रखी होती। वे देहात छोड़कर शहर में आते हैं। उनके लिए शहर में रहने के लिए कोई इन्तजाम नहीं होता।

न नगरों में नौकरी का इंतजाम है। वहां झोपड़ी-पट्टी का सवाल शुरू होता है। जैसे बम्बई, कलकत्ता और जितने भी बड़े शहर हैं उनमें यह हालत उन लोगों की है कि जो देहात छोड़कर आये हैं उनके लिए न रहने का इंतजाम है, न रोजगार का इंतजाम है जहां भी वह रहते हैं, झोंपड़ी-पट्टी खड़ी करते हैं। न राशन मिलता है, न राशन कार्ड देने के लिए कोई तैयार है, न और सुविधाएं हैं। रास्ते के किनारे ये लोग रहना शुरू करते हैं और फिर समाज विद्रोही ऐंटीसोशल-ऐलिमेंट शुरू होता है। शहरों की जो कुछ समस्याएं शुरू होती हैं जिसके लिए बड़े गौर से सोचना चाहिए इस सदन में। इस लिए मेरा सुझाव यह है कि पहले तो आपको यह करना चाहिए कि देहात में जो अर्द्ध बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ रोगगार ग्रामीण क्षेत्रों में ही शुरू करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक स्कीम उन्होंने शुरू की थी और ऐलान किया था कि रूरल इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम शुरू की जायेगी। श्री बी० भगवती साहब जो बेरोजगार समिति के चेयरमेन थे उन्होंने बड़े गौर से अपनी इस रिपोर्ट में निर्देश दिया है पार्ट ए 64 पेज पर, कि दूसरी स्टेट में भी यह योजना शुरू करना जरूरी है।

उप-सभापति महोदय मैं अदब के साथ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस स्कीम के बारे में कहा गया है लेकिन वह स्कीम अभी तक कार्यान्वित इंप्लीमेंट नहीं हुई है। चुनाव के टाइम वह ऐलान किया था महाराष्ट्र सरकार ने कि यह स्कीम हम वहां शुरू करने जा रहे हैं। मैं उस समय विरोधी दल का नेता था। मैंने कहा था कि यह आप कर नहीं सकते हैं, यह एक इलेक्शन स्लोगन है। मगर यह चीज पेपर पर आ गई, परन्तु चुनाव हुए दो साल हो गए अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई। सदन के मालूमात के लिए मैं बताऊंगा कि इसकी स्कीम क्या थी। बेरोजगार लोग पहले ग्राम पंचायत को बताएं कि उनको काम चाहिए। गांव पंचायत अपने कार्यक्षेत्र में काम शुरू करे मगर सौ डेढ़ सौ आदमी वहां हो गये कि फिर पंचायत समिति जो बड़ी रहती है, वह

कितने लोगों को काम चाहिए यह देखकर अपने ब्लाक में उस हिसाब से काम शुरू करें । लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि न ग्राम पंचायत काम दे सकती है, उनके पास पैसा भी नहीं है और जो पंचायत समिति विस्तृत क्षेत्र पर रहती है उनके पास भी पैसा नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वह भी काम नहीं दे सकती । फिर यह योजना सिर्फ कागज पर ही रहेगी । मेरी विनती मंत्री महोदय से यह है कि देहातों में आपको काम शुरू करना चाहिए । मगर पंचवर्षीय योजना जो महाराष्ट्र की हो गई है उन्होंने पैसा रखा है 10 करोड़ रुपया पांच साल के लिए । मैं जिस कमेटी का सदस्य था, अग्रिकल्चरल लेबरर्स मीनिमम वेजेज कमेटी उसमें हमने जो स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किये हैं उनसे पता लगता है कि महाराष्ट्र में 54 लाख खेत मजदूरों को काम की जरूरत है । 3-4 महीने के बाद उनको खेती का काम नहीं मिलता है । 10 करोड़ रुपये 5 साल के लिए रखा है । उसका हिसाब लगायें तो कम से कम 50 लाख लोगों को काम देने की कोशिश की जाये और दो रुपया हर एक को मिले तो एक करोड़ रुपया एक दिन में और दो करोड़ रुपया दो दिन में मजूरी बांटनी पड़ेगी । इस प्रकार पूरी पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ का इंतजाम किया है । मेरी विनती यह है मंत्री महोदय से कि अगर इन लोगों को अर्द्ध-रोजगार जो लोग हैं, उनको अगर काम देना है तो फिर स्टेट को पैसा देना होगा ।

दूसरी बात यह है कि स्कीमें कौन कौन सी हैं उनको सामने रखकर ज्यादा पैसा देना होगा । एक सवाल तो यह है और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग देहात छोड़कर शहर की तरफ आते हैं वे अपना वतन छोड़कर खुशी से शहर में नहीं आते । उनको ग्रामीण विभाग में रोजगार मिले तो खुशी होगी । उसके बारे में चन्द शब्द कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । उपसभापति महोदय, (*Time bell rings*) यह मेरी मेडन स्पीच है इस लिए मुझ को कुछ अधिक समय दिया जाए । यह बहुत जरूरी सवाल है इस लिए ही मैं इसको उठा रहा हूं अन्यथा मैं इसको नहीं उठाता । सवाल यह है कि देहाती लोग रोजी-रोटी के लिए जाते हैं शहरों में और गवर्नमेंट भी चाहती है और प्लानिंग कमीशन भी चाहता है कि देहातों में ज्यादा कारखानेदार जायें । लेकिन देहातों में कारखाने खोलने के लिए आप देखें कि क्या किया जाना चाहिए । उन के लिए कुछ सुविधाएं रखी गई हैं लेकिन इतनी सुविधाएं रखे जाने के बावजूद भी फैक्टरी वाले देहात के पिछड़े इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उनको लाइसेंस और परमिट क्यों दिया जाता है? मैं उपसभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी यह सवाल उठाया गया था कि बंबई में और पूना में और नागपुर में अब बहुत सी फैक्टरियां हो गई हैं और अब उन लोगों को स्टेट के पिछड़े इलाकों में जाना चाहिए । लेकिन वह लोग उन इलाकों में नहीं जाते और मानते नहीं हैं और गवर्नमेंट ने जो उनकी पुरानी फैक्टरियां हैं उनके एक्सपैंशन के लिए परमिशन दी है और उन को नयी फैक्टरियां लगाने की सुविधा भी दी है । इतना ही नहीं, वहां नया बंबई बनना शुरू हो गया है जहां और ज्यादा फैक्टरियां लगाने की कोशिश हो रही है । तो मेरी मंत्री महोदय से विनती यही है कि किसी भी कारखानेदार को अगर परमिट देना हो या कोई लाइसेंस देना हो तो उस के लिए पहली कंडीशन यह होनी चाहिए कि उसको पिछड़े इलाकों में जाना होगा । हमारे भाई ने अभी एक बात उठायी थी कि राजस्थान के लोग यहां दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं । हमारे यहां यही समस्या है । पूरे भारत के लोग काम की तलाश में बंबई जाते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं और उनके कारण प्रान्तीयवाद बढ़ता है । मैं वहां पहले ही शिवसेना के खिलाफ था और मैंने असेम्बली में सब से पहले उन के खिलाफ आवाज बुलन्द की थी, परन्तु समस्या हल नहीं हुई । उसके लिए रास्ता निकालना चाहिये । अगर हर इलाके में और हर स्टेट में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में ही फैक्टरियां शुरू की जायें तो उन में 80 परसेंट लोकल आदमियों को काम और रोजगार मिलना चाहिए और फिर यह स्वाल पैदा नहीं होगा । पूरे हिन्दुस्तान के लिए हमने यह "80 परसेंट स्थानीय मजदूरों को काम" इस योजना पर कार्यवाही की तो प्रान्तीयवाद का सवाल भी कम पैदा होगा । तो जितने सुझाव मैंने रखे हैं उन पर मुझे आशा है कि मंत्री जी गौर करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

The House then adjourned at thirteen minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th April, 1974.